राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 2217/2024

कुलदीप पुत्र महावीर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी सालीवाला पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. चिरंजीलाल पुत्र फूसाराम, निवासी सालीवाला पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. किरण पुत्री चिरंजीलाल, उम्र लगभग 21 वर्ष, पत्नी -कुलदीप, निवासी पुलिस थाना टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री निशांत मोत्सरा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह – पीपी
श्री तरुण ढाका शिकायतकर्ताओं के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>02/08/2024</u>

1. सम तिथि के संक्षिप्त आदेश के तहत, इस याचिका को आज सुबह खुली अदालत में दलीलें सुनने के बाद अनुमति दी गई। इसके कारण और अन्य विवरण तत्काल अलग आदेश के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। धारा 458, 365, 363 और 323 आईपीसी के तहत कथित अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज एफआईआर संख्या 0040/2020 दिनांक 16/02/2020 के साथ-साथ विद्वान विशेष न्यायालय, पोक्सो अधिनियम मामलों, हनुमानगढ़ के समक्ष सत्र मामला संख्या 36/2020 में आगे की कार्यवाही लंबित है।

2. सर्वप्रथम याचिका से सुसंगत तथ्य। प्रतिवादी संख्या 2 (पिता) ने आरोप लगाया कि दिनांक 15/02/2020 को प्रातः लगभग 03:00 बजे वह अपनी पुत्री

की चीख सुनकर अचानक जाग गया। उसने देखा कि आरोपी कुलदीप उसका अपहरण करने का प्रयास कर रहा था। जब वह उसे रोकने के लिए उठा तो कुलदीप ने उसके साथ मारपीट की तथा उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया। इस रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान पुलिस ने लड़की का पता लगाया तथा याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया। लड़की की आयु 18 वर्ष से कुछ माह कम होने के कारण वह नाबालिग थी, अतः बाद में उसके विरूद्ध पोक्सो अधिनियम की दण्डात्मक धाराएं भी लगाई गई।

2.1. आरोप-पत्र में कहा गया है कि पीड़िता/प्रतिवादी संख्या 3 ने धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान दिनांक 26.02.2020 और उसके बाद धारा 164 के तहत दिनांक 03.03.2020 के बयान में याचिकाकर्ता के साथ कई मौकों पर शारीरिक संबंध स्थापित करने का उल्लेख किया है। उक्त बयान के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 366 और 376 आईपीसी और धारा 5 एल/6 पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध का पता चला, जबकि धारा 365 सीआरपीसी के तहत अपराध का पता नहीं चला। इस प्रकार आरोपी-याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 458, 363, 366, 323 और 376 आईपीसी और धारा 5 एल/6 पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दिनांक 27/04/2020 को आरोप पत्र दायर किया गया।

2.2. विद्वान निचली अदालत द्वारा दिनांक 30/05/2020 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुकदमे के दौरान, लड़की/अभियोक्ता वयस्क हो गई। फिर उसने अपनी मर्जी से अपना साथी चुनने के अपने अधिकार का प्रयोग किया और 21/12/2021 को याचिकाकर्ता के साथ विवाह कर लिया। तब से वे पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। युवा पत्नी/अभियोक्ता वर्तमान में अपने परिवार में है और विवाह से एक बच्चे को जन्म देने वाली है।

2.3. दूसरी ओर आपराधिक कार्यवाही पहले की तरह जारी है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए हैं और ट्रायल चल रहा है। शिकायतकर्ता और पीड़िता के साथ-साथ अन्य गवाहों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। अब मामले में आरोपी के बयान दर्ज किए जाने हैं।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 पिछले ढाई साल से खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। वह 13/12/2022 के विवाह प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हैं। गर्भावस्था रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3 छह सप्ताह की

गर्भवती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने नीचे की विद्वान अदालत के समक्ष हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने परिवार के सदस्यों की इच्छा के अनुसार सीआरपीसी की धारा 161/164 के तहत अपने पहले के बयान दिए थे। प्रासंगिक समय पर, उन्होंने याचिकाकर्ता से शादी करने के उसके इरादे को मंजूरी नहीं दी। अब पूरा परिवार याचिकाकर्ता के साथ उसकी शादी को मंजूरी देता है। नाबालिग होने के कारण उसके पास उनके दबाव की रणनीति के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा, याचिकाकर्ता के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से सहमति और आपसी पसंद से था। इसलिए एफआईआर और परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए, उन्होंने आग्रह किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा अवधेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 7901/2023 मामले में दिनांक 05/01/2024 के निर्णय पर भरोसा किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने तरुण वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 6323/2022, दिनांक 13/10/2022 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार) में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए याचिका को स्वीकार किया और एफआईआर के साथ-साथ पोस्को अधिनियम के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया।

5. प्रतिवादी-शिकायतकर्ताओं के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक भी विवाह के तथ्य से सहमत हैं। वे संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि विवाह को देखते हुए, यदि संबंधित एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. अपहरण के आरोप के संबंध में, मेरा विचार है कि आईपीसी की धारा 366 को पढ़ने से यह पता चलता है कि नाबालिग या महिला को कानूनी अभिभावक (नाबालिग के मामले में) की हिरासत से दूर ले जाना, अपने आप में अपहरण का अपराध नहीं बनता है। बेहतर समझ के लिए, धारा 366 आईपीसी नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है: -

> धारा 366 किसी महिला को विवाह के लिए बाध्य करने के लिए उसका अपहरण या व्यपहरण करना, आदि-
>
> जो कोई किसी महिला का अपहरण इस आशय से करता है कि उसे किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया

जाएगा, या ताकि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा;

और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी या अधिकार के दुरुपयोग या मजबूरी के किसी अन्य तरीके से, किसी महिला को किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है, इस आशय से या यह जानते हुए कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करने के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, वह भी पूर्वोक्त रूप से दंडनीय होगा। ”

7. उपरोक्त धारा को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि इसका दायरा न केवल अपहरण या व्यपहरण के कृत्य को शामिल करता है, बल्कि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए धमकी, डराने या अधिकार का उपयोग भी करता है। इसका उद्देश्य उन मामलों में इसे लागू करना है, जहां किसी महिला की पसंद की स्वतंत्रता से समझौता किया जाता है। इस प्रकार आईपीसी की धारा 366 महिलाओं को विवाह के लिए मजबूर किए जाने या यौन शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य अपहरण, व्यपहरण या धमकी के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का प्रयास करने वालों को दंडित करके महिलाओं की गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखना है। हालांकि, केवल अपहरण आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि अपहरण का कार्य उसे “उसकी इच्छा के विरुद्ध” विवाह करने के लिए मजबूर करने या बल का प्रयोग करने या उसे अवैध संबंध/संभोग के लिए प्रेरित या बहकाने के इरादे से किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, दम्पति के बीच संबंध उसके ले जाए जाने से पहले के थे और उसके बाद, उन्होंने स्वेच्छा से एक दूसरे से विवाह कर लिया। इस प्रकार धारा 366 की कोई भी सामग्री आकर्षित नहीं होती।

8. कुछ इसी तरह की परिस्थिति में, जहाँ एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था और धारा 366 के बजाय, धारा 361 आईपीसी लगाई गई थी (जैसा कि इस मामले में भी होना चाहिए था, क्योंकि लड़की प्रासंगिक समय पर नाबालिग थी), सर्वोच्च न्यायालय ने 1964 में एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य (1965) 1 एससीआर 243 नामक अपने फैसले में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

"7. यह प्रश्न कि क्या नाबालिग अपने अभिभावक की संरक्षकता को त्याग सकता है और यदि ऐसा है तो आगे का प्रश्न कि क्या सावित्री ने अपने पिता की संरक्षकता को त्याग दिया है, इसका उत्तर देना शायद बहुत आसान नहीं है। सौभाग्य से, हालाँकि, हमारे लिए उनमें से किसी का भी उत्तर देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम अपने सामने उठाए गए दूसरे प्रश्न पर जो दृष्टिकोण रखते हैं, वह यह है कि सावित्री को उसके पिता की देखभाल से "छोड़ना" सिद्ध नहीं हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के प्रथम पैराग्राफ में "वैध संरक्षण से अपहरण" के अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> "जो कोई किसी नाबालिग को, यदि वह पुरुष है तो सोलह वर्ष से कम आयु का, या यदि वह महिला है तो अठारह वर्ष से कम आयु का, या किसी विकृत चित्त वाले व्यक्ति को, ऐसे नाबालिग या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के वैध संरक्षक की देखरेख से, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना, ले जाता है या बहलाता है, तो उसे ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षण से अपहरण करना कहा जाता है।"

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि नाबालिग को वैध अभिभावक की निगरानी से दूर ले जाना या बहला-फुसलाकर ले जाना अपहरण के अपराध का एक अनिवार्य घटक है। यहां, हमारा संबंध बहलाने-फुसलाने से नहीं है, बल्कि हमें यह पता लगाना है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका सावित्री को वैध अभिभावक की निगरानी से दूर ले जाने के बराबर है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हालांकि सावित्री को एस. नटराजन ने अपने रिश्तेदार के. नटराजन के घर पर छोड़ दिया था, फिर भी वह वैध अभिभावक की निगरानी में थी, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि अपीलकर्ता ने ऐसा क्या किया जो कानून में "ले जाना" माना जाता है।

... ...

9. हालांकि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि नाबालिग को किसी व्यक्ति के साथ ले जाने और उसे अनुमति देने में अंतर है। ये दोनों अभिव्यक्तियाँ समानार्थी नहीं हैं, हालाँकि हम यह कहने से बचना चाहेंगे कि किसी भी कल्पनीय परिस्थिति में इन दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के प्रयोजनों के लिए एक ही अर्थ नहीं

माना जा सकता। हम खुद को वर्तमान जैसे मामले तक सीमित रखेंगे, जहाँ नाबालिग को आरोपी व्यक्ति द्वारा ले जाया गया था, जो अपने पिता के संरक्षण को छोड़कर स्वेच्छा से आरोपी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, यह जानते हुए कि वह क्या कर रही थी और उसे यह जानने की क्षमता है। ऐसे मामले में हमें नहीं लगता कि आरोपी व्यक्ति के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह उसे उसके वैध अभिभावक की देखभाल से दूर ले गया है। इस तरह के मामले में कुछ और भी दिखाया जाना चाहिए और वह है आरोपी व्यक्ति द्वारा किसी तरह का प्रलोभन दिया जाना या नाबालिग द्वारा अभिभावक के घर छोड़ने के इरादे के निर्माण में उसकी सक्रिय भागीदारी। (जोर दिया गया)

8. धारा 376 के आरोप के संबंध में, धारा 5एल/6 के साथ पॉक्सो अधिनियम के अनुसार, यह एक बार फिर किसी अपराध का मामला नहीं लगता है। बल्कि मामले के स्व-व्याख्यात्मक तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह याचिकाकर्ता और अभियोक्ता के बीच सहमति से संबंध था, लेकिन दुर्भाग्य से वह विवाह योग्य आयु से कुछ महीने कम थी, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता कानून के टकराव में आ गया और इस प्रकार, वह एक कथित अपराधी बन गया।

9. जो भी हो, वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि न तो अभियोक्ता के माता-पिता और न ही अभियोक्ता स्वयं अपने दामाद यानी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप लगाना चाहते हैं। दूसरी ओर, राज्य ऐसे मुकदमे का अनावश्यक बोझ उठा रहा है, जहां दोषसिद्धि की संभावना उज्ज्वल नहीं दिखती।

10. दोषसिद्धि की अप्रत्याशित स्थिति में, यह मानते हुए कि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा तरुण वैष्णव बनाम राज्य एवं अन्य (एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 6323/2022, दिनांक 13.10.2022 को निर्णीत) के मामले में मेरे विद्वान भाई दिनेश मेहता, जे. की अध्यक्षता में दिए गए निर्णय के अंश का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:-

"17. विभिन्न उच्च न्यायालयों ने स्थिति के चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक पहलुओं से निपटने, पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का विश्लेषण करने, तथा नवजात शिशु के भविष्य सहित व्यावहारिक वास्तविकताओं पर विचार करते हुए अलग-अलग तर्क दिए हैं।

18. इस न्यायालय को लगता है कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए एफआईआर को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना उचित मामला है, क्योंकि:-

(i) एक किशोर लड़की (16 वर्ष) को 22 वर्ष के लड़के से प्यार हो गया है;

(ii) दोनों अपरिपक्व होने के कारण, क्षणिक भावनाओं से प्रेरित होकर, सामाजिक, नैतिक और कानूनी सीमाओं को पार करते हुए वासना का शिकार हो गए हैं;

(iii) शिकायतकर्ता पुलिस है और लड़की या उसका परिवार न तो पीड़ित पक्ष है और न ही शिकायतकर्ता;

(iv) लड़की अपने इस रुख पर कायम है कि उसने शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी थी। न केवल धारा 161 और धारा 164 के तहत अपने बयानों में, बल्कि इस न्यायालय के समक्ष भी, लड़की ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने इस कृत्य के लिए सहमति दी थी;

(v) उनका व्यभिचार, भले ही कानूनी और नैतिक स्वीकृति के बिना हो, बच्चे को जन्म देने के परिणामस्वरूप हुआ है;

(vi) दोनों के माता-पिता - लड़की और लड़के ने अपने-अपने बच्चों को उनके अपराध के लिए माफ कर दिया है, जब अभियोक्ता विवाह योग्य आयु प्राप्त कर लेती है, तो उन्हें विवाह सूत्र में बांधने का इरादा रखते हैं;

(vii) यदि अभियोग जारी रहता है, तो याचिकाकर्ता को दोषसिद्धि का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की नाबालिग है। दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप 10 साल की कैद होगी, जो न्याय सुनिश्चित करने के बजाय लड़की और उसके नवजात बेटे के लिए और अधिक पीड़ा और दुख लाएगी;

(viii) और इसलिए भी कि दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मूल तत्व - "गलत व्यक्ति के लिए बदला लेना" पूरी तरह से अनुपस्थित है।

19. ऐसी स्थिति का सामना करते हुए और समग्र परिस्थितियों के मूल्यांकन के बाद, एक अपवादात्मक मामले के रूप में, यह न्यायालय प्रार्थना के अनुसार याचिका को स्वीकार करने के लिए राजी है। याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन देवनगर, जोधपुर शहर (पश्चिम) में दर्ज की गई एफआईआर संख्या 0260/2022 को न केवल समझौते के आधार पर, बल्कि ऊपर वर्णित कारणों और सुनवाई के दौरान जो कुछ भी हुआ है, उसके आधार पर भी रद्द किया जाता है।

11. वर्तमान मामले के तथ्य उक्त निर्णय के पैरा संख्या 18 में बताए गए तथ्यों के समान हैं। इस प्रकार, न्याय के व्यापक हित में और पक्षकारों को वैवाहिक सुख का आनंद लेने और आगे की सुनवाई की बदनामी के बजाय शांतिपूर्वक और खुशी से रहने में सक्षम बनाने के लिए, हाथ में मौजूद एफआईआर और उसके बाद होने वाली कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

12. परिणामस्वरूप, याचिका, जैसा कि पहले ही माना गया है, स्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप, पुलिस स्टेशन टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज की गई एफआईआर संख्या 0040/2020 दिनांक 16/02/2020 और उससे उत्पन्न सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।